नई शिक्षा नीति 2020 : समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा

डॉ. प्रीति कछावा,

सहायक आचार्य, रघुकुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जयपुर।

Corresponding Email: preetikachhawa59@gmail.com

शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। शिक्षा पर सभी का अधिकार है अतः शिक्षा का अब समावेशीकरण हो रहा है जिसमें सबको समाहित कर ले, ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो अर्थात् हर वर्ग के सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में एक विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। समावेशन सबके लिए सामान्य स्कूल के प्रत्यय को स्पष्ट करती है। यह एक ऐसा शैक्षिक प्रतिरूप है, जो सार्वभौमिक समाज के निर्माण एवं विकास के उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति को समान जगह देता है। यूनेस्को ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन, जेनेवा (2008) में समावेशी शिक्षा पर चर्चा की ओर स्पष्ट किया कि समावेशी शिक्षा छात्रों के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक अधिकार पर आधारित है जो आधारभूत शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर जीवन को समृद्ध बनाती है। समावेशी शिक्षा समाज के हर वर्ग के प्रतिभाशाली कमजोर औसत, मानसिक रूप से कमजोर बालकों के लिए है जिससे वे समाज धारा में जुड़ते हैं आत्मविश्वासी होती है। इसका उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत की नई शिक्षा नीति इन्हीं लक्ष्यों को लेकर प्रस्तावित की गई है।

मुख्य शब्द : शिक्षा, निति, समता मूलक, समावेशी शिक्षा

नई शिक्षा नीति 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी। NEP 2020 द्वारा स्कूली एवं उच्च शिक्षा प्रणालियों में रूपान्तरकारी सुधारों का रास्ता साफ हुआ है जिसमें समावेशी एवं समता मूलक शिक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा है। शिक्षा में पहुंच, सहभागिता और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अन्तरालों को दूर करना सभी शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। NEP 2020 के अध्याय 6 एवं अध्याय 14 में समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा की गई है। भारतीय शिक्षा प्रणाली और सरकारी नीतियाँ विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों में

लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अन्तरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगतिशील है परन्तु आज भी शिक्षा तक सबकी पहुंच बाकी है विशेषकर माध्यमिक स्तर पर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह है जो शिक्षा के क्षेत्र में पहले से ही पिछड़े हुए हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह (एस. ई. डी. जी.) को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है –

- (i) लिंग – महिला एवं ट्रांसजेंडर व्यक्ति
- (ii) सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान – SC, ST, OBC एवं भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक

- (iii) भौगोलिक पहचान ग्रामीण क्षेत्र, कस्बे व आंकांक्षी जिलों के विद्यार्थी
- (iv) विशेष आवश्यकता — सीखने सम्बन्धी अक्षमता
- (v) सामाजिक आर्थिक स्थिति — प्रवासी समुदाय, निम्न आर्थिक वर्ग असहाय, अनाथ बच्चे, बाल एवं मानव तस्करी का शिकार, शहरी गरीब

स्कूलों में आज भी कक्षा 1 से कक्षा 12 तक लगातार नामांकन घट रहा है नामांकन में यह गिरावट सामाजिक-आर्थिक स्थिति के वंचित समूहों में आई है। NEP 2020 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। NEP 2020 के अध्याय 3-4 के अनुसार बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित एवं व्यवहारिक पहुंच एवं छात्रों को कक्षा से जोड़े रखना महत्वपूर्ण कार्य होगा, इसमें विशेषकर यह व्यवस्था लड़कियों एवं सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए की गई है। NEP 2020 के पैरा 6.2 के अनुसार अनुसूचित जातियों के बीच नामांकन और प्रतिधारण की दरों पर, गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुंच पाने में कमी, गरीबी सामाजिक रीति रिवाजों और प्रथाओं और भाषा सहित अनेक विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ा है अतः इसके प्रमुख लक्ष्यों में से एक अनुसूचित जातियों के बच्चों की पहुंच

भागीदारी और अधिगम परिणामों में इन अन्तरालों को पूरा करना है। साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों और विशेष रूप से उन समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप के महत्व को स्वीकार किया गया है जिसका शैक्षिक रूप से प्रतिनिधित्व कम है। स्कूली शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अन्तराल को कम करने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किये गये हैं जिसमें जेण्डर समावेशी कोष (पैरा 6.8) की स्थापना की गई है इसे बालक-बालिकाओं को सामाजिक मापदण्डों और घरेलू कार्यों तक ले जाना है, लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में समस्याओं और बाधाओं की पहचान करनी है। जेण्डर समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे उनको ऐसी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी जिसमें महिलाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षापूर्ण व स्वस्थ वातावरण मिल सके जैसे परिसर में महिला शौचालयों को स्थापित करना स्वच्छता एवं सेनिटेशन से सम्बन्धित अन्य सुविधाएं प्रदान करना, स्कूल आने-जाने के लिए साईकिल देना, फीस न भर पाने की स्थिति में अभिभावकों को सशर्त नगद हस्तान्तरण करना ताकि वे गरीबी के कारण स्कूल छोड़ने पर मजबूर न हो सकें। इससे महिलाओं का नामांकन बढ़ेगा। ऐसे स्थान जहां छात्रों को अधिक दूरी

तय करनी पड़ती है वहां जवाहर नवोदय विद्यालय के स्तर की तर्ज पर निशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा, विशेषकर सामाजिक – आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले बालकों के लिए। कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों को और अधिक मजबूत एवं विस्तृत किया जाएगा जो कि बालिका शिक्षा के लिए भारत सरकार की पहले से ही एक महत्वपूर्ण योजना है। भारत के हर कोने में उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा के अवसरों के लिए अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय व केन्द्रीय विद्यालय खोले जायेंगे। केन्द्रीय विद्यालयों में व देश के अन्य प्राथमिक विद्यालयों में विशेषकर वंचित क्षेत्रों में प्री-स्कूल वर्ग को जोड़ा जायेगा।

NEP 2020 में दिव्यांग बच्चों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना प्राथमिकता के रूप में लिया गया है। दिव्यांग बच्चों को प्रारम्भिक स्तर से उच्चतर स्तर तक की शिक्षण प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए सक्षम बनाया जायेगा। यह नीति दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत होगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा तैयार करते समय NCERT द्वारा दिव्यांगजन विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों से भी परामर्श लिया जायेगा। दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखने हुए विद्यालय व विद्यालय परिसरों की वित्तीय मदद के प्रावधान किये जायेंगे तथा वहां विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। गंभीर एवं एक

से अधिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए संसाधन केन्द्र खोले जायेंगे कक्षा कक्ष में उनकी पूर्ण सहभागिता व समावेशन सुनिश्चित करने के लिए सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीक आधारित उपकरण, भाषा उपयुक्त शिक्षण सामग्री बेल लिपि में सुलभ पुस्तकें, बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जायेगी इसके अतिरिक्त दिव्यांग बच्चों के लिए गृह आधारित शिक्षा (Home Schooling) भी एक विकल्प होगा। गृह आधारित शिक्षा के तहत शिक्षा ले रहे बच्चों को सामान्य शिक्षा ले रहे बच्चों के समतुल्य माना जाएगा और इसकी प्रभावशीलता व क्षमता की जांच हेतु क्षमता व अवसर की समानता के सिद्धान्त पर आधारित आडिट कराया जायेगा। प्रत्येक बच्चे की क्षमता का लाभ लेने के लिए पाठ्यक्रम को प्रत्येक के लिए सक्षम व लचीला बनाना तथा उपयुक्त आंकलन एवं प्रमाणन के लिए इकोसिस्टम बनाना प्रमुख लक्ष्य है। नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र परख नाम से स्थापित किया गया। पारम्परिक एवं धार्मिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को NTA द्वारा राज्य या अन्य बोड़ परीक्षाओं और मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जायेगा। पुस्तकालयों व प्रयोगशालाओं को मजबूत किया जायेगा। स्कूल शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों के तहत सभी सामाजिक एवं आर्थिक रूप में वंचित श्रेणी के प्रतिभाशाली व मेधावी छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर समर्पित क्षेत्रों में विशेष छात्रावास ब्रिज पाठ्यक्रम और फीस माफ करने

तथा छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता विशेषकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जायेगी जिससे उच्च शिक्षा में उनका प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में राज्य सरकारों को जनजाति बहुल प्रदेशों सहित अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में NCC विंग खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति अवसर और योजनाओं से प्रतिभाग करने की दृष्टि से सिंगल विण्डो प्रणाली स्थापित की जायेगी।

इसी प्रकार NEP 2020 में उच्चतर शिक्षा में समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले महत्वपूर्ण कुछ नीतिगत पहलू अपनाए जायेंगे जैसे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए समुचित निधि एवं स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण, उच्च शिक्षा में जेण्डर संतुलन को बढ़ावा देना, विकासोन्मुख जिलों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों का निर्माण, स्थानीय भारतीय भाषाओं में शिक्षण, छात्रवृत्ति के अवसर, बेहतर भागीदारी एवं सीखने के परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण एवं विकास उच्चतर शिक्षा में उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी शिक्षा को समावेशी एवं समतामूलक बनाने के लिए कदम उठाए जायेंगे जैसे उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को रोजगार परक बनाना, छात्रवृत्ति के अवसर उपलब्ध करवाना,

प्रवेश प्रक्रिया व पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना, वंचित वर्ग के लिए ब्रिज पाठ्यक्रमों की शुरुआत, छात्रों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, भेदभाव एवं उत्पीड़न के खिलाफ नियमों को सख्ती से लागू करना, संस्थागत विकास योजनाओं का निर्माण, भाषायी डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, सलाह एवं परामर्श कार्यक्रमों का आयोजन करना।

उपयुक्त सभी महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करने के बाद हम यह जान पाए की नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा ऐसे लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ती है जिससे भारत देश के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से सम्बन्धित परिस्थितियाँ बाधक न हो। इस प्रकार यह नीति हमारे देश के आने वाले शैक्षिक भविष्य के लिए सुधारात्मक एवं समन्वयात्मक नीति सिद्ध होगी।

सन्दर्भ :

- नई शिक्षा नीति 2020 की रूपरेखा, अनुच्छेद 6 व 14
- मिश्रा, मृत्युन्जय, एक समावेशी विद्यालय का निर्माण अरिहंत शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
- Pandey, S.P. & Mansoori, Imtiyaz (2019), Creating an inclusive school, R. Lal Book Depot Meerut.
- www.education.gov.in> NEP 2020 MHRD.
- www.drishtiias.co